

जब तक आप किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह काम नामुमकिन ही लगता है।

TODAY WEATHER



DAY 32°
NIGHT 28°
Hi Low

संक्षेप

बिहार में बाढ़ से 50 लाख लोग प्रभावित, शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव मदद का दिया भरोसा

पटना, एजेंसी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का विस्तृत जायजा लिया और संकट से निपटने में राज्य की मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। चौहान ने हाजीपुर में ग्रामीण आजीविका को हुए भारी नुकसान का आकलन किया और पाया कि कई जगहों पर पानी का स्तर 2016 की बाढ़ के समय के स्तर से भी ऊपर चला गया है, जिससे पूरे बिहार में लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। शिवराज ने पत्रकारों से कहा कि वे कह रहे हैं कि पानी का स्तर 2016 की बाढ़ से भी एक फ़ीट ज्यादा था। हम देख सकते हैं कि यहीं केले और मकई की फ़सलें बर्बाद हो गई हैं और लगातार 10 दिनों से ज्यादा समय तक पानी में डूबे रहने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े—पूरे बिहार में लगभग 50 लाख (5 मिलियन) लोगों को। फ़सलों को नुकसान पहुँचा है, घरों को नुकसान पहुँचा है, और कुछ लोग मवेशियों के नुकसान की भी बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हालात का खुद जायजा लेने के लिए बिहार भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय टीमें पहले से ही हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि यहीं केले और मकई की फ़सल को नुकसान पहुँचा है क्योंकि वे लगातार 10 दिनों से ज्यादा समय तक पानी में डूबी रही हैं। पूरे बिहार में लगभग 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।

15,012 पदों पर निकली भर्ती, असिस्टेंट टीचर और पीजीटी के लिए ओटीआर जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। अलग-अलग राज्यों में कथित पेपर लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच युवाओं तक पहुँचने की कोशिश करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले छह महीनों में 1 लाख युवा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सीपीपी। 'मिशन रोजगार' के तहत कृषि विभाग में 3,446एच युगे गए टैक्निकल असिस्टेंट (गु-सी) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा चुने गए 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक सभा की संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भेदभाव के 9.30 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों दी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 15,012 टीचर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। आयोग के चैयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने 15 सितंबर को ये विज्ञापन जारी किया। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले जरूरी वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा, जिसके बाद वे अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। कुल खाली पदों में से 897 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी से जुड़े) के हैं, जबकि 11,508 पद बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर (शहरी) के हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करने के लिए कोलकाता में हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम का जन्मदिन 17 सितंबर को है। ठीक इसके 20 दिन बाद सार्वजनिक जीवन के उनके 25 साल पूरे होंगे। सरकार की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने कहा किहमने जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन और कम गवर्नेंस वाली सोच को बदल दिया है। हमने इसे सही रेगुलेशन और अच्छी गवर्नेंस वाला बनाया है। यही 'मोदीनॉमिक्स' है। मोदी को समझने के लिए आपको भारत को समझना होगा। मोदी की असली पूंजी लोगों का भरोसा है। पीसी में राजनाथ सिंह ने यूपीआई पर भी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं उन्होंने किस मुद्दे पर क्या

दवा की असली कीमत से कितनी ज्यादा महंगी दवा खरीदते हैं आप : तुकाराम मुंडे

नई दिल्ली, एजेंसी। अस्पताल में इलाज कराने के दौरान मरीज के हाथ में जो बिल आता है, उसमें कई ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जिनकी असली खरीद कीमत शायद ही मरीज को पता होती है। अब महाराष्ट्र के IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने एक पोस्टर के जरिए मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमत और उनकी ट्रेड प्राइस के बीच के अंतर पर सवाल उठाया है। उन्होंने महाराष्ट्र के एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि 11 IS0 रुपये के IV इन्फ्यूजन सेट को MRP 325 रुपये थी। अस्पताल का बिल देखते वक्त क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मेडिकल सामान के लिए आप भुगतान कर रहे हैं... अस्पताल ने उसे कितने में खरीदा होगा? महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने इसी सवाल को उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के अस्पतालों में मेडिकल



कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें UPI के बारे में भी बात करनी चाहिए। शुरू में इसका विरोध हुआ था। UPI के जरिए 23। 66 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने UPI की तारीफ की है। सड़क किनारे सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) ने UPI से अपनी आमदनी बढ़ाई है। काम

करने का तरीका बदला है। एक स्टार्टअप ने पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है?

100 देश खरीदते हैं हमारे डिफेंस प्रोडक्ट

पीएम मोदी दुनिया के सबसे

'कारगिल, पीओके और सर क्रीक देने की थी तैयारी'

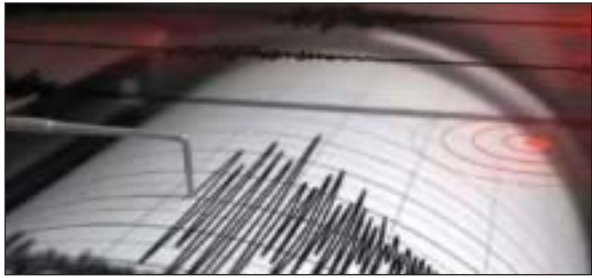
निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप, हवाना बैठक का दिया हवाला



निशिकांत दुबे ने 16 सितंबर 2006 को हवाना में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच हुई मुलाकात का हवाला दिया। उन्होंने इस बैठक को अमेरिका के दबाव में हुई कूटनीतिक पहल बताया। दुबे के मुताबिक, यह मुलाकात ऐसे समय हुई थी जब जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से देश में

भारी आक्रोश था। इन धमाकों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग घायल हुए थे और कई लोगों को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा था। दुबे का आरोप है कि हमलों के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने सैन्य जवाब देने के बजाय बातचीत के जरिए तनाव कम करने का रास्ता चुना।

बाढ़ के बाद भूंकप से सहमा नेपाल देर रात महसूस किए गए दोहरे झटके



करीब ढाई घंटे बाद फिर कांपी धरती

पहले झटके के बाद सुबह करीब 4:28 बजे 4.2 तीव्रता का दूसरा भूंकप दर्ज किया गया। इस भूंकप का केंद्र भी मुगु जिले के कलाई के पास ही स्थित था। लगातार दो झटकों से इलाके के लोगों में चिंता पैदा हो गई।दोनों भूंकप

के झटके पड़ोसी डोल्पा और जुम्ला जिलों में भी महसूस किए गए। भूंकप के बाद स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना, हालांकि अधिकारियों ने तत्काल किसी के घायल होने या किसी इमारत को नुकसान पहुंचने की सूचना से इनकार किया है।

पाकिस्तानी जहाज अरब सागर में भारतीय युद्धपोत से टकराया : तेज रफ्तार से गलत दिशा में मुड़ा था, दिल्ली में पाक हाईकमिश्नर तलब



विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण वर्ष 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिक गतिविधियों की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते के अनुच्छेद 10 के सीधे विपरीत था। भारत की आपर्ति का सबसे अहम पहलू यही है कि सैन्य गतिविधियों में शामिल इकाइयों से केवल पेशेवर

दक्षता ही नहीं, बल्कि स्थापित समझौते और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के कठोर पालन की अपेक्षा की जाती है। देखा जाये तो समुद्र में दो देशों की सैन्य इकाइयों की मौजूदगी अपने आप में संवेदनशील होती है और ऐसे में मामूली चूक भी गंभीर सुरक्षा संकट का रूप ले सकती है। नई दिल्ली में पाकिस्तान के राजनयिक प्रतिनिधि को स्पष्ट संदेश

दिया गया कि वह इस मामले को संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। भारत ने सैन्य इकाइयों को समुद्र में आवश्यक सावधानी बरतने और दोनों देशों के बीच लागू समझौतों का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसी के साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी मुद्दे पर औपचारिक विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

हम आपको बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अरब सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

पाकिस्तान नौसेना ने सितंबर की शुरुआत में समुद्री युद्धाभ्यास शुरू किया था, जिसका उद्देश्य उसकी युद्धक तैयारी को परखना बताया गया था। पाकिस्तानी नौसेना के समुद्री चेतावनी अभिलेखों में भी अगस्त-सितंबर के दौरान अरब सागर में विभिन्न सैन्य और समुद्री गतिविधियों के उल्लेख मिलते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसा मामला पहली बार सामने नहीं आया है। वर्ष 2011 में भी भारत ने पाकिस्तानी नौसैनिक पोत बाबर द्वारा भारतीय नौसेना के पोत गोदावरी के आसपास जोखिमपूर्ण गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया था और उस समय भी 1991 के इसी समझौते के अनुच्छेद 10 का हवाला दिया गया था।

यूपीआई चार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एमडीआर के खिलाफ याचिका दायर

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में यूपीआई शुल्क के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर को जारी उन गैजेट नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है, जिनमें 2000 से ज्यादा के कर्मशियल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई थी। यह याचिका वकील अंजन दत्ता ने इस आधार पर दायर की है कि हाल ही में घोषित चार्ज का असर आखिरकार आम नागरिकों पर पड़ेगा। यह याचिका केंद्र सरकार, RBI, नेशनल पैमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और यूपीआई के खिलाफ दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही इन चार्जों को मामूली और यूपीआई प्लेटफॉर्म को बनाए रखने के लिए जरूरी बताया जा रहा हो। चाहे फीस सीधे प्लेटफॉर्म या सर्वेंट पर ही क्यों न लगाई जाए, आम जनता पर इसका असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने से कैश पेमेंट को बढ़ावा मिल सकता है।

स्टार्टअप हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या सिर्फ 500 थी। डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट में 56% की बढ़ोतरी हुई

है। यह आंकड़ा 1। 08 लाख करोड़ रुपये का है। 100 देश हमारे डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं।

मिसाइल दाग दो, मैं अकेला खड़ा रहूंगा ..., असदुद्दीन ओवैसी की भाजपा एमएलए रामेश्वर शर्मा को चुनौती

नई दिल्ली, एजेंसी। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में यूनिकर्नर्स सिविल कोड (UCC) के विरोध में एक जनसभा को संबोधित करते हुए BJP विधायक रामेश्वर शर्मा को खुली चुनौती दी। उन्होंने भोपाल के काजी कैप पर मिसाइल दागने के शर्मा के कथित बयान पर कहा कि वह उस इलाके में अकेले खड़े होकर इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, हैदराबाद के सांसद ने मध्य प्रदेश के BJP विधायक के कथित बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विधायक ने कथित तौर पर कहा था कि वह करोड़ स्वयंराज से भोपाल के अल्पसंख्यक-बहुल काजी कैप इलाके की ओर मिसाइल दांगेंगे।



असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रामेश्वर शर्मा, अगर हिम्मत है तो बताओ, तुम मिसाइल कब लॉन्च करोगे? मैं काजी कैप में अकेला खड़ा रहूंगा। मैं शहीद होने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों के सामने सिर झुकने को तैयार नहीं हूँ। रामेश्वर शर्मा को काजी कैप का इतिहास पता होना चाहिए। आखिर यह काजी कैप क्या है? ओवैसी ने सवाल किया कि रामेश्वर शर्मा, सुनो कि काजी कैप क्या है।

गवाहों की पहचान गुप्त रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने HPEC से कहा कि जो संवेदनशील या कमजोर गवाह अपनी बात रखने के लिए सामने आए, उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए। गवाहों के बयान और उनके द्वारा दिए गए सबूतों को भी पूरी तरह गोपनीय रखने को कहा गया है। इसके लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि गवाह और दूसरे संबंधित लोग दस्तावेज और सबूत जमा कर सकें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने जंतर-मंतर पर छत्र प्रदर्शन के मामले की जांच के लिए हाई पावर्ड कमिटी बनाने का एलान किया था।

दो वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. मोंनिका गुप्तेन, वरिष्ठ अधिवक्ता और सी. सोलोमन, AOR को Amici Curiae नियुक्त किया है। ये कोर्ट की सहायता करेंगे, HPEC के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे और पक्षों के बीच स्वतंत्र

मध्यस्थ की भूमिका भी निभाएंगे।कोर्ट ने HPEC से जल्द से जल्द Member Secretary नियुक्त करने को भी कहा है, ताकि कमिटी को प्रशासनिक और दूसरे जरूरी कामों में मदद मिल सके। कोर्ट ने HPEC से अपनी पहली रिपोर्ट जल्द दाखिल करने को कहा है।

जिन गांव वालों के उजाड़े थे घर, अब उन्हीं ने अपनाने से किया इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटें ऐसे कुछ हथियारबंद नक्सलियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है। जिन्होंने दहशत के दिनों में अपने ही गांव वालों का खून बहाया था। अब आत्मसमर्पण कर चुके यह नक्सली जब अपने गांवों में जा रहे हैं तो गांववाले इनकी खुली मुखालफत करते हुए इन्हें अपनाने से इंकार कर रहे हैं। गांव वालों का तर्क है कि खून-खराबे के दौर में जब इन्होंने जिसे चाहा उसे पुलिस का मुखबिर बताकर कितने ही घरों को उजाड़ दिया तो अब इन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? मामले में छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के एसपी मयंक गुर्जर ने भी एनबीटी को बताया कि सरेंडर किए हुए कुछ नक्सलियों के सामने इस तरह की समस्या आई हैं। जिन्हें गांव वालों से बातचीत करके दूर किया जा रहा है

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का कहना है कि अब वह किसी भी सूरत में हथियार नहीं उठाएंगे, वस उन्हें उनके गांव में भी जगह मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। इसके लिए पुलिस-प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि सरेंडर कर चुके नक्सलियों को अब कोई समस्या ना आने पाए। पुलिस प्रशासन इनके रोजगार के लिए भी लगातार काम कर रहा है। ताकि इनके सामने रोजी-रोटी का भी संकट पैदा ना होने पाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यूं तो देश में जितने भी राज्यों में हथियारबंद नक्सली थे। उनमें से कुछ मारे गए तो अधिकतर ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन झारखंड में अभी भी 20-25 नक्सलियों के एक-दो ग्रुप अभी बचे हुए हैं।

आर्यावर्त क्रांति

राजीव से राहुल तक का सफर भी कम गौरतलब नहीं

हेरों प्रमाण हैं। तारीखों और घटनाओं का वह अंतहीन सिलसिला है जिससे मेरा निष्कर्ष है कि भारत के कम्युनिस्टों ने न केवल देश का समय बिगाड़ा। खुद के अवसर भी गंवाए। लेफ्ट के ख़ाते में राजनीतिक बरबादियां लगातार दर्ज कराईं। बावजूद इसके मेरे मन में कम्युनिस्ट नेताओं के चाल, चेहरे और चरित्र की कसौटी में सम्मान है। खासकर आज सत्ता में संघ-भाजपाइयों के चाल, चेहरे और चरित्र को देखते हुए तो और भी अधिक। उस नाते ई. एम. एस. नंबूदरीपाद, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्त से माणिक सरकार, पिनराई विजयन और वाम संगठनों के प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य तक—इन लोगों की निजी सादगी, सहजता और वैचारिक प्रतिबद्धता का जितना सम्मान किया जाए, कम है।

मगर व्यक्ति की ईमानदारी से विचार और उसके परिणाम सही साबित नहीं होते। भारतीय कम्युनिस्टों का विरोधाभास यही है। निजी जीवन में जितने सादे और प्रतिबद्ध, भारत को पढ़ने में उतनी ही बार गड़बड़। स्वतंत्रता के बाद कम्युनिस्टों ने आजादी को अंधूरा माना। कांग्रेस को बुर्जुआ सत्ता कहा। नेहरू को कभी वर्ग-शत्रु की राजनीति में पढ़ा और कभी उन्हीं के आसपास घेरबंदी से उन पर वैचारिक प्रभाव बनाया। नेहरू के आखिरी सालों में कृष्ण मेनन और चीन से भारत की हार का ठीकरा भी फूटा। चीन के सवाल पर ही कम्युनिस्ट विभाजित हुए। दो पार्टियां बनीं। इंदिरा गांधी के दौर में सीपीआई उनके साथ थी। उसका आपातकाल को समर्थन रहा। फिर जनता पार्टी, बी. पी. सिंह, संयुक्त मोर्चा और यूपीए—दिल्ली में सत्ता के गठजोड़ बने तब भी वामपंथी चेहरों, पार्टियों का सरकारों, राष्ट्रीय नरैटिव और मीडिया में हल्ला रहा।

लेकिन एक बात, एक वास्तविकता हमेशा कायम रही। केंद्र सरकार की सत्ता के आसपास विचार, बौद्धिकता और विमर्श की दुनिया में वाम की हैसियत उसकी असल जन हैसियत, पाए गए लेफ्ट वोटों से अक्सर कई गुना बड़ी रही। सोचे, कृष्ण मेनन के प्रभाव और 1962 के अनुभव यानी लेफ्ट से नेहरू ने क्या पाया? कांग्रेस के 1969 के विभाजन के बाद वाम समर्थन और वाम-प्रगतिशील बौद्धिक प्रभाव की ओर बड़ी इंदिरा गांधी अंततः कहाँ पहुँची? वैक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स, गरीबी हटाओ, सरकारी उद्योगों-उद्यमों, लाइसेंस-कोटा से कांग्रेस और भारत ने क्या पाया? लगातार फेलते सरकारी दायरे में उल्टे कांग्रेस अपनी पुरानी मध्यमार्गी अर्थनीति से लेफ्ट की ओर खिसकती गई। तात्कालिक फायदे की राजनीति में भले इंदिरा को गरीबों की मसीहा की इमेज मिली। कांग्रेस का नया सामाजिक आधार बना। मगर उसी के साथ सरकार अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन की सर्वशक्तिमान माई-बाप बनती गई।

ऐसे ही इंदिरा गांधी के समय विश्वविद्यालयों, इतिहास, संस्कृति, अकादमिक संस्थानों, मीडिया और दिल्ली के नीति-विमर्श में लेफ्ट का नया प्रगतिशील प्रतिष्ठान बना। सही है, उसमें बैठे सभी लोग कम्युनिस्ट नहीं थे। लेकिन आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील कहलाने की खास भाषा जरूर सभी चेहरों-मटाथीशों—शिक्षा मंत्री, उपकुलपतियों, कला-साहित्य-संस्कृति आदि क्षेत्रों में—की थी। उस भाषा, उस सोच में धर्म को सार्वजनिक जीवन में लेकर चलने वाला हिंदू आसानी से रूढ़िवादी करार दिया जाता। जबकि धार्मिक अल्पसंख्यक की सामुदायिक पहचान की रक्षा सेकुलर राज्य का दायित्व। जाति पर बात करना प्रगतिशीलता, वही सनातनी धर्म और सभ्यता पर बात करते हुए सफाई देती हुई झिझक। इसलिए 'लेफ्ट का अर्थ, उसके जुगालीबाजों का दायरा बहुत विस्तृत रहा है। बात केवल सीपीआई, सीपीएम या सीपीआई-एमएल का पार्टी कार्ड रखने वालों की ही नहीं है। समाजवादी कम्युनिस्ट नहीं थे। लोहियावादी और मार्क्सवादी एक नहीं थे। अंबेडकरवादी भी कम्युनिस्ट नहीं। एनजीओ एक्टिविस्ट और अधिकारवादी नागरिक समाज को भी कम्युनिस्ट कहना गलत होगा। इन सबके आपसी झगड़े और वैचारिक फर्क गहरे हैं। लेकिन समय के साथ लुटियंस दिल्ली में इन धाराओं के मेल से एक व्यापक वाम-प्रगतिशील सत्ता-बौद्धिक मानस की दबंगी बनी। समाज को वर्ग, जाति, लिंग, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक और उत्पीड़क-उत्पीड़ित के खंांचों से देखने की प्रवृत्ति पूरे देश में पसरती गई। यही मेरे 'लेफ्ट के आशय का व्यापक वैचारिक खमीर है। मगर कमाल या त्रासदी देखिए। लेफ्ट का रौब, हल्ला जैसे-जैसे बढ़ा, वैसे-वैसे कम्युनिस्टों, वामपंथियों, समाजवादियों की चुनाबी और वैचारिक हैसियत जीरो होती गई। वोट में सिकुड़ते गए, लेकिन उनकी बनाई भाषा, जुमलों के फतवे बढ़ते गए। एक वक्त था जब संसद में दर्जनों संसद थे। संसद में कांग्रेस के बाद सीपीआई नंबर दो की पार्टी! बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सरकारें। ट्रेड यूनियनों में दबदबा। विश्वविद्यालयों में प्रभाव। संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन कभी राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी शक्ति था। पश्चिम बंगाल में चौतौस साल सरकार थी।

व्यंग्य

बांग्लादेश की सामरिक दिशा के ठोस संकेत



पाकिस्तान की मुख्य भूमिका वाले समझौतों से जुड़ने की इच्छा और चीनी हथियार प्रणालियों को खरीदने का फैसला बांग्लादेश की नई सामरिक दिशा के ठोस संकेत हैं। भारत को इससे उचित संदेश ग्रहण करना चाहिए।

बांग्लादेश ने पुष्टि कर दी है कि वह चीन में बने 4.5वीं पीढ़ी के जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। इसके अलावा वह चीनी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, वीआईसी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, और ड्रोन्स की खरीदारी भी करेगा। इसका अर्थ है कि अब बांग्लादेश चीन अस्त्र प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहा है। इस फैसले का औचित्य बताते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जियाउर रहमान ने जो कहा, उस पर भारत को अवश्य ध्यान देना चाहिए। रहमान ने कहा कि पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान खबर मिली कि पाकिस्तान ने जे-10सीई के जरिए भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उसे ध्यान में रखते हुए ही बांग्लादेश ने उन विमानों को खरीदने का फैसला किया है।

कुछ ही रोज पहले बांग्लादेश ने मक्का सुरक्षा समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई। हालांकि इस समझौते में शामिल देशों से बांग्लादेश को कोई न्योता नहीं मिला है, मगर संसद में विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा कि अगर आमंत्रण मिलता है, तो उस पर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री तारिक रहमान से विचार करेगा। मक्का समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब, और तुर्किये के बीच हुआ है। ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया में बदली सामरिक स्थितियों के बीच उस क्षेत्र में नई उभरती सुरक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान की भूमिका ठोस ढंग से बढ़ रही है।

बीते हफ्ते कुवैत ने भी अपनी सेना को प्रशिक्षित करने, खुफिया जानकारी साझा करने, तथा रक्षा तकनीक और सीमा प्रबंधन में सहयोग के लिए पाकिस्तान से नया सैन्य समझौता किया। पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जोड़ने के खाड़ी देशों की ताजा सोच के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, और दूसरा उसकी तीन चौथाई हथियार प्रणालियां का चीनी सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के पाकिस्तान से आम संबंध गहरे हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तान की मुख्य भूमिका वाले समझौतों से जुड़ने की इच्छा और चीनी हथियार प्रणालियों को खरीदने का फैसला उसकी सामरिक दिशा के ठोस संकेत हैं। भारत को इससे उचित संदेश ग्रहण करना चाहिए।

संपादकीय

गुरुवार, 17 सितंबर, 2026

तो अब शुभेंदु करेंगे गरबा मर्यादा की भी रक्षा?

तरुण विजय
 जिस प्रकार शुद्ध हिंदू उत्सव गरबा में गैर हिंदुओं को शामिल करने की विकृत सेकुलर आवाजें उठने लगीं हैं उनको देखते हुए लगता है कि मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में होने वाले गरबा उत्सवों की मर्यादा रक्षा के लिए तेजस्वी हिंदू ध्वज वाहक एवं पश्चिम बंगाल के महानायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सहायता मांगने का समय आ गया है .अब सब हैं कि सेक्युलर तालिबानी आवाजों के विरुद्ध हिंदुओं को चाहिए कि अपना अंगद समान पैर जमाया जाए। बंगाल से सीख ली जाए, जहाँ तेजस्वी वीर हिंदू नायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दुर्गा पूजा को उसकी मूल गरिमा लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे सीखकर गरबा को पतन से बचाया जाए। गरबा शक्ति की उपासना से जुड़ा पारंपरिक हिंदू पूजा-स्वरूप है। यह धनकुबेरी और हिंदू-भावना विहीन भीड़ के लिए मस्ती-मस्ती का कार्निवल नहीं है। गरबा कोई सेक्युलर मनोरंजन "मेला" नहीं है। यह माँ अम्बा की भक्ति का हिंदू प्रतीक है। जो माँ दुर्गा की पूजा नहीं करते, जो उनके सामने शीश नहीं झुकाते, उनको गरबा में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं। इसका मूल रूप और अर्थ हिंदू ब्रह्मांड-दृष्टि, प्रतीकों और दिव्य स्त्री-शक्ति की साधना से आता है।
"गरबा" शब्द संस्कृत शब्द "गर्भ" से निकला है। पारंपरिक रूप में नर्तक एक घेरे में गर्भ दीप या दुर्गा की मूर्ति के चारों ओर नृत्य —या देवी की मूर्ति के चारों ओर नृत्य अभ्यर्थना करते हैं। दीपक जीवन-शक्ति, शरीर के भीतर दिव्य उपस्थिति और देवी की सृजन-शक्ति का प्रतीक है। वृत्ताकार गति हिंदू चिंतन में काल के चक्र—सृष्टि, स्थिति और प्रलय—को दर्शाती है।
गरबा शरद नवरात्रि में होता है, अर्थात् दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित नौ रातों में। यह पर्व महिषासुर पर दुर्गा की विजय का स्मरण है, जैसा देवी माहात्म्य (मार्कंडेय पुराण) में वर्णित है। भक्त माँ की स्तुति के गीत (गर्बी) गाते हैं, ताली देते हैं और नृत्य को पूजा तथा हृतज्ञता का माध्यम बनाते हैं। पारंपरिक माहौल में स्थान पवित्र माना जाता है: प्रायः नंगे पैर नाचते हैं,

ब्लॉग

देसी राज की शिक्षा ने मतिहीन नेता बनाए

शंकर शरण
 हिन्दू ग्रंथों की निन्दा करने वाले उसे शायद ही पढ़ते हैं। मनुस्मृति के राज्य-शासन संबंधी तीनों अध्याय गंभीर ज्ञान-भंडार हैं। अधिकांश आज भी मूल्यवान्‌। तब सोचे, तीन हजार वर्ष पहले इतना गहन चिंतन विश्व में कहाँ था ! तब यहाँ ऐसे शास्त्र रचे गए, जिन की बातें आज भी चमकृत करती है। ँ चिंदक लोग केवल सुनी-सुनाई पर चलते हैं कि उस में 'शूद्रों या स्त्रियों के बारे में कुछ आपत्तिजनक है। वस्तुतः मनुस्मृति में वैसा भी कुछ नहीं है।.. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति को अपने समाज-सुधार का आधार बनाया था। यदि मनुस्मृति जातिवादी या स्त्री-विरोधी होती, तो वे संपूर्ण भारत में इतना बड़ा आधुनिक, व्यापक प्रभावशाली सुधार आंदोलन चलाने में कैसे सफल हुए होते ? प्रायः लगता है, कि अंग्रेजों ने इस देश को अधिक सहानुभूति से समझा था। लोगों की ही नहीं, अपितु यहाँ के ज्ञान, इतिहास, विरासत, धर्म और संस्कृति के प्रति भी सच्ची देख-भाल की प्रवृत्ति उन में थी। यह बात एकबारगी विचित्र लगे, किंतु ठोस पैमानों पर — सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक — परखने से सोचने पर विवश होना पड़ेगा।
शिक्षा का उदाहरण लें। अंग्रेजों ने यहाँ अपने बनाए स्कूलों, कॉलेजों में यूरोप के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से भारतीय बच्चों, युवाओं को शिक्षित किया। सहित्य और दर्शन में महान भारतीय रचनाओं को भी वही स्थान दिया। यह पुराने पुस्तकालयों में रखी उस जमाने की पाठ्य सामग्रियों तथा उस युगीन हमारे विद्वानों के लेखन के माध्यम से भी जाना जा सकता है।
पर देशी राज की शिक्षा ने क्या किया? इस ने जल्द ही शिक्षा का राजनीतिकरण, मतवादीकरण कर दिया ! पूरे ब्रिटिश राज में शायद ही स्कूलों में कभी ब्रिटिश सम्राटों या वायसरायों की विरुदावली पढ़ाने, फैलाने का काम हुआ। देशी राज में अपने चालू नेताओं को दैवी, जानी, चिंतक, विश्वनेता, आदि बताना नीचे से ऊपर सभी कक्षाओं में एक सामान्य तत्व बन गया। यह प्रवृत्ति शिक्षा के विरुद्ध कुशिक्षा को प्रश्रय देना था। अनजाने होने से उस की हानि कम नहीं हुई ! बल्कि फिर उस का प्रतिफलन, विस्तार, आदि अन्य क्षेत्रों में भी होना ही था।
जैसे, शिक्षा में सच्चे सिद्धांत पढ़ने के बजाए वैसे मतवादों, विचार पढ़ाना जो उन नेताओं को पसंद थे। या जो उन की अपनी झक थीं। तदनुसार, विद्वानों के बदले उन भक्तों और रटू तोतों को आचार्य, अध्यापक, संचालक बनाना जो उन मतवादों का प्रचार करें। इसी तरह, फिर शोध के नाम पर उन्हीं बातों, आग्रहों, दुराग्रहों की पुष्टि

आरती होती है, और केंद्र में दीपक या मूर्ति ही मुख्य रहती है।

नवरात्रि व्रत माँ भगवती की भक्ति का चिह्न है। गरबा और डांडिया रास (जहाँ डंडे देवी के आयुधों के प्रतीक हैं) गुजरात में इसी भक्ति की सामाजिक अभिव्यक्ति बने।

लोक-नृत्य के रूप में यह शादियों और अन्य अवसरों पर भी होता रहा है, पर इसका सबसे विस्तृत और मुख्य संदर्भ दुर्गा-पूजा का नवरात्रि चक्र ही है। क्योंकि यह रूप देवी और उनके प्रतीकों के इर्द-गिर्द बुना गया है, पारंपरिक हिंदू साधक और संगठन इसे श्रद्धा का कर्म मानते हैं, सेक्युलर-गैरहिंदू मनोरंजन नहीं। जो दुर्गा को दिव्य माता नहीं मानते, मूर्ति-पूजा और धर्मिक विश्वास को अस्वीकार करते हैं, वे इस अनुष्ठान के उद्देश्य से बाहर हैं। गरबा को सिर्फं "फन मेला" कहना उसे उसके धर्मिक अर्थ से काट देता है और पूजा-भक्ति को तमाशा बना देता है। अन्य धर्मों के अनुष्ठानों से तुलना स्वाभाविक है। इंद की नमाज़ इस्लामी मजहब के अनुसार निर्धारित है। गैर-मुसलमानों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे औपचारिक नमाज़ में मजहबी कर्तव्य के रूप में शामिल हों; वह स्थान और स्वरूप उन लोगों का है जो उस आस्था को स्वीकार करते हैं। अनेक परंपराओं में मूल उपासना-कर्म की सीमाएँ ऐसी ही हैं। नवरात्रि में गर्भ दीप या दुर्गा की मूर्ति के चारों ओर होने वाला गरबा उसी श्रेणी का आस्था-विशिष्ट कर्म है, राज्य द्वारा थोपा गया खुला सांस्कृतिक मेला नहीं। आज कई स्थानों पर गरबा अव्यधिक व्यावसायिक हो चुका है और हिंदू-भावना विहीन इवेंट मैनेजर्स के हाथों विकृत हो रहा है। समय आ गया है कि अंगद समान हिंदू आस्था और मर्यादा का पैर जमाया जाए। बंगाल से सीख ली जाए, जहाँ तेजस्वी वीर हिंदू नायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दुर्गा पूजा को उसकी मूल गरिमा लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे सीखकर गरबा को पतन से बचाया जाए।

यूनेस्को ने 2023 में गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। उसमें इसके हिंदू सामाजिक स्वरूप और शक्ति/स्त्री-ऊर्जा के वृत्त को बनाए

रखते हुए लोगों को जोड़ने की क्षमता का उल्लेख है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का कहना सही है कि यह देवी-पूजा का रूप है, इसलिए प्रवेश उन्हीं का हो जो इस आस्था को साझा करते हैं। गरबा स्थलों पर प्रवेश नियंत्रण और पहचान जैच की माँग इसीलिए है। मिश्रित आयोजनों में तनाव, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने, अपमान और उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आई हैं। गैर-हिंदुओं द्वारा हिंदू देवताओं का मज़ाक उड़ाने और "गरबा के बहाने हिंदू लड़कियों को छेड़ने" की खबरें भी आती रही हैं। हिंदुओं को समावेशिता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं। भारत का संविधान हिंदू-बहुल ज़माने में बना। यह कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता और प्रत्येक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है। भारतीय संविधान हिंदू समावेशिता की अभिव्यक्ति है। गरबा सनातन धर्म की मर्यादा से बंधा है। हिंदू अपनी संवेदनाओं के अनुरूप प्रवेश की शर्तें रख सकते हैं। मंदिर, मठ और पारंपरिक संप्रदाय पहले से कुछ अनुष्ठान-स्थानों पर मर्यादा के अनुसार प्रवेश नियंत्रित करते हैं। दुर्गा-पूजा पर आधारित सामुदायिक गरबा पर भी वही तर्क लागू होना चाहिए। अब साधु-संन्यासियों और पारंपरिक हिंदू स्वरो से अपील करनी चाहिए कि वे विशिष्ट हिंदू रूपों की मर्यादा स्पष्ट करें और उसकी रक्षा करें। ये माँग धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल हैं। शास्त्रीय नवरात्रि रूप में गरबा दुर्गा भगवती—माता और शक्ति के स्वरूप—के प्रति भक्ति का हिंदू अनुष्ठान है। गर्भ-दीप, वृत्ताकार गति, स्तुति-गीत तटस्थ मनोरंजन नहीं हैं। जो यह विश्वास नहीं रखते, वे इसके धार्मिक उद्देश्य से बाहर हैं, जैसे गैर-मुसलमानों के इवेंट की औपचारिक नमाज़ की संरचना से बाहर हैं। अनुष्ठान के पारंपरिक स्वरूप की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि नृत्य की व्यापक लोकप्रियता से इनकार किया जाए। अर्थ यह है कि पूजा-केंद्रित कर्म अपने आप खुली सेक्युलर पार्टी नहीं बन जाता। जो आयोजक इसे उपासना मानते हैं, उन्हें भागीदारी का ढाँचा उसी के अनुसार रखने का अधिकार है।	आदि कहलाने का हकदार हो जाता है। यह है देसी राज की शिक्षा का नतीजा, जिस में पैदा हुए और पले-बढ़े लोग ही आज देश भर में सत्तासीन हैं। वे न केवल यह दृश्य सहज रूप से देखते हैं, अपितु इसी को प्रोत्साहन देते हैं। मामूली खोजबीन से ऐसे उच्च पदस्थ लोग मिल जाएंगे जो मनुस्मृति को जलाकर, या उसे अपशब्द कह कर ऊपर स्थापित हुए। साथ ही, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो जटिल विषयों के अच्छे ज्ञाता हैं, इसीलिए कहीं भूखे, बेघर उपेक्षित पड़े हैं। जो किन्हीं मित्रों के अनुदान और सहयोग से जीवन चला रहे हैं। क्योंकि वे उस 'कैटेगरी के हैं जिन की जरूरत देसी राज को नहीं है। सो, देसी राज में महान पुस्तकें शिक्षा से क्रमशः बाहर होती गईं। उन्हें तुच्छ या अशरंगिक मान लिया गया। बिना पढ़े। मनुस्मृति की नियमित भस्ती इस का उदाहरण है। जबकि यदि शीर्षक हटाकर इसे किन्हीं भी दस समझदार लोगों को पढ़ने को दें, और फिर मंतव्य लें, तो सभी उसे महान ग्रंथ मानेंगे। अतः निंदक लोग केवल सुनी-सुनाई पर चलते हैं कि उस में 'शूद्रों या स्त्रियों के बारे में कुछ आपत्तिजनक है। वस्तुतः मनुस्मृति में वैसा भी कुछ नहीं है। यदि होता, तब भी आज के नजरिए से किसी पुरानी पुस्तक में कोई नापसंद बात मिलने पर भी उसे अपमानित करना मूर्खता है। इसीलिए 'ओल्ड टेस्टामेंट या 'कुरान जैसे प्राचीन ग्रंथों को सम्मान दिया जाता है। जबकि उस में पगान, आइडोलेटर, काफिर, यानी दूसरे धर्म-विश्वासियों के लिए अत्यंत अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। उस दृष्टि से आज दुनिया में कम से कम तीन अरब लोग आइडोलेटर और काफिर हैं। तो मनुस्मृति को गाली देने की तर्ज पर आइडोलेटरों को क्या इन्हें उन पुस्तकों को अपशब्द कहने का अधिकार है? पूछ कर देखिए, मनुस्मृति को जलाने का दंभ रखने वाले बगलें झाँकने लगेंगे! देसी राज की शिक्षा ने ऐसे ही मतिहीन नेता बनाए हैं। जो अपनी ही दलील से दो कदम भी सुसंगत नहीं चल सकते। पर वही हमारे कर्त्ता-धर्ता और मार्गदर्शक हैं। मनुस्मृति में सृष्टि, दर्शन, धर्म-निर्तन, जीवन के विधि-विधान, गृहस्थ-जीवन, स्त्री, विवाह, राज्य-राजा संबंधी परामर्श, वैश्य-शूद्र संबंधी कर्तव्य, प्रायश्चित, कर्मफल विधान, मोक्ष और परमात्मा चिंतन हैं। विविध प्रकाशनों में मनुस्मृति में डेढ़ से लेकर ढाई हजार श्लोक मिलते हैं। उन में सैकड़ों प्रक्षिप्त श्लोक माने गए काफिर, यानी दूसरे धर्म-विश्वासियों के लिए अत्यंत अपमानजनक बातें विस्तृत लगे। उन पर विद्वानों में मतभेद हैं। अतः किसी एक मात्र प्रमाणिक प्रति पर असहमति है। फिर भी, ध्यान देना चाहिए कि स्वामी दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्द की तमाम शिक्षाओं और जीवन-कर्म का आधार वेद, उपनिषद और मनुस्मृति हैं। इस प्रकार, भारतीय
---	--



